

Think
IAS...



Think
Drishti

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC)

भारतीय अर्थव्यवस्था

(मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ सहित)

भाग-2

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम (Distance Learning Programme)

Code: MPPM14



मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC)

भारतीय अर्थव्यवस्था

(मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ सहित)

भाग-2



641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

दूरभाष : 8750187501, 011-47532596

टोल फ्री : 1800-121-6260

Web : www.drishtiIAS.com

E-mail : online@groupdrishti.com

पाठ्यक्रम, नोट्स तथा बैच संबंधी updates निरंतर पाने के लिये निम्नलिखित पेज को "like" करें



www.facebook.com/drishtithevisionfoundation



www.twitter.com/drishtiiias

9. राजकोषीय नीति एवं बजट व्यवस्था	5-61
9.1 बजट व्यवस्था	5
9.2 केंद्रीय बजट 2020-21	20
9.3 भारत में कराधान	30
9.4 वस्तु एवं सेवा कर	35
10. विदेशी व्यापार	62-84
10.1 विदेशी व्यापार : सामान्य परिचय	62
10.2 विदेशी व्यापार की संरचना	67
10.3 निर्यात संवर्द्धन	69
10.4 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते	74
10.5 विदेश व्यापार नीति, 2015-20	79
11. भुगतान संतुलन	85-106
11.1 भुगतान संतुलन : अर्थ एवं अवधारणा	85
11.2 भुगतान शेष प्रबंधन	91
11.3 रुपए की परिवर्तनीयता	96
11.4 विदेशी निवेश	99
11.5 विदेशी पूंजी का नियमन	102
12. अंतर्राष्ट्रीय संगठन	107-149
12.1 संयुक्त राष्ट्र संघ	107
12.2 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन	109
12.3 विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, अंकटाड, यूनेस्को, यू.एन.डी.पी., जी-20	119
12.4 सार्क, ब्रिक्स, बिस्सटेक, आसियान, एपेक, शंघाई सहयोग संगठन	126
12.5 न्यू डेवलपमेंट बैंक (ब्रिक्स बैंक), एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, एशियाई विकास बैंक	132
12.6 गुट-निरपेक्ष आंदोलन, नाटो	134
12.7 अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं समूह	137

13. नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र के मुद्दे	150–184
13.1 अवसंरचना	150
13.2 निम्न आय वर्गीय समूह के लिए आवास	151
13.3 नगरीय क्षेत्र के मुद्दे : शहरीकरण से उपजी समस्याएँ	153
13.4 शहरी अवसंरचना : आवास, स्वच्छता और अवसंरचना विकास योजनाएँ	155
13.5 ग्रामीण अवसंरचना : आवास, स्वच्छता और अवसंरचना विकास योजनाएँ	166
13.6 ग्रामीण साख	177
14. सहकारिता आंदोलन	185–193
14.1 सहकारिता : सामान्य परिचय	185
14.2 भारत में सहकारिता आंदोलन	186
14.3 मध्य प्रदेश में सहकारिता आंदोलन	188
15. योजनाएँ	194–236
15.1 केंद्र सरकार की योजनाएँ	194
15.2 मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएँ	222
15.3 विविध	228
16. आर्थिक अवधारणाएँ तथा शब्दावलियाँ	237–240

राजकोषीय नीति एवं बजट व्यवस्था (Fiscal Policy and Budget System)

अर्थशास्त्री कींस की पुस्तक **द जनरल थ्योरी ऑफ इन्फ्लॉयमेंट एंड मनी** में प्रतिपादित विचारों में एक विचार यह भी है कि सरकार को राजकोषीय नीति का प्रयोग निर्गत और रोजगार को स्थिर करने के लिये किया जाना चाहिये। कींस के अनुसार सरकार को करों तथा व्यय में परिवर्तनों के माध्यम से राजकोषीय नीति द्वारा अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने का प्रयास करना चाहिये।

राजकोषीय नीति से तात्पर्य कर, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण का प्रबंध किन्हीं सुनिश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति करने से है।

भारत की राजकोषीय नीति के वृहद् उद्देश्यों के अंतर्गत संतुलित एवं तीव्र विकास, कल्याणकारी राज्य की स्थापना और समाजवादी ढंग के समाज की रचना करना इत्यादि शामिल हैं। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये निम्नलिखित राजकोषीय नीतियाँ अपनाई गई—

- ग्रामीण आधारीय संरचना पर पूंजीगत व्यय में वृद्धि करना ताकि कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ाया जा सके।
- पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त करने के लिये प्रयास करना।
- सार्वजनिक क्षेत्र की घाटे में चल रही इकाइयों में विनिवेश की प्रक्रिया जारी रखना।
- राजकोषीय घाटे को निकट भविष्य में यथासंभव शून्य करना।
- राजकोषीय घाटे को संघ और राज्य के लिये क्रमशः 3% और 2% से कम करना।
- महत्त्वहीन वस्तुओं (Non Merit Goods) पर दी जा रही सब्सिडी को कम करना एवं वैसी छिपी हुई सब्सिडी भी घटाना जो समर्थ लोगों को अधिक लाभ पहुँचा रही है।
- भुगतान संतुलन की स्थिति प्राप्त करने के लिये प्रयास करना।

9.1 बजट व्यवस्था (Budget System)

सरकार राजकोषीय नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये बजट व्यवस्था के अंतर्गत अपने आय-व्यय को समायोजित करती है। बजट एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। भारतीय संविधान में 'बजट' शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। संविधान में बजट के लिये **वार्षिक वित्तीय विवरण** अभिव्यक्ति का प्रयोग किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 112 (1) के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिये अनुमानित प्राप्तियाँ एवं व्यय का विवरण रखवाएगा। इस वार्षिक वित्तीय विवरण को केंद्र सरकार का बजट कहा गया है।

बजट में लगातार तीन वर्षों के व्ययों तथा प्राप्तियों का विवरण दिया रहता है।

1. आने वाले वर्ष के लिये बजट अनुमान। इसका अर्थ है कि यदि वर्ष 2017-18 में बजट पेश किया जा रहा है तो वर्ष 2018-19 का अनुमान।
2. चालू वर्ष के लिये संशोधित अनुमान। यदि वर्ष 2017-18 का बजट पेश हो रहा है तो यह इस साल के लिये अस्थायी अनुमान उपलब्ध करवाना।

स्मरणीय बिंदु

- स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर, 1947 को प्रथम वित्त मंत्री आर.के. षण्मुखम चेट्टी द्वारा पेश किया गया।
- जॉन मथाई को वर्ष 1950 में भारतीय गणतंत्र का पहला केंद्रीय बजट पेश करने का गौरव हासिल हुआ।

संशोधित अनुमान: यह बजट के आकलन अथवा अस्थायी आँकड़ों का वर्तमान आकलन होता है। यह वर्तमान आँकड़ों की स्थिति को दर्शाता है। ये अंतरिम आँकड़े हैं।

विजयराघवगढ़ के सरयू प्रसाद सिंह	विजयराघवगढ़, मध्य प्रदेश के कटनी ज़िले का एक कस्बा है। विजयराघवगढ़ के राजा सरयू प्रसाद ने मात्र 17 वर्ष की उम्र में 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों के विरुद्ध बगावत शुरू की थी। वास्तव में युवराज सरयू प्रसाद सिंह क्रांतिकारी विचारधारा के एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। 1857 के क्रांतिकारी ने जब बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित किया और दिल्ली पर अधिकार कर लिया तब विजयराघवगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य था जिसने तोपें दागकर क्रांति का अभिनंदन किया था और विदेशी सत्ता को चुनौती दी थी। सन् 1865 में सशस्त्र सैनिकों के पहरे पर काले पानी की सज़ा के लिये 'रंगून' जाते समय यह वीरात्मा पहरेदार की कटार छीनकर अपने सीने में भोंककर शहीद हो गए। उन्होंने कहा था कि 'मैं काला पानी से मौत को अधिक पसंद करता हूँ। मेरी प्रजा में तुच्छ से तुच्छ व्यक्ति भी जेल में रहना पसंद नहीं करता फिर मैं तो उनका राजा हूँ।' उन्हें सेना से निकालकर उनकी गिरफ्तारी के आदेश जारी कर दिये गए। जैसे ही रणमत सिंह को पता चला तो वह 300 देशभक्त सैनिकों को लेकर निकल पड़े व अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह में शामिल हो गए। इन्होंने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को विस्तृत करते हुए बघेलखंड तथा बुंदेलखंड के बाहर छत्तीसगढ़, छोटानागपुर तथा नर्मदा अंचल के सलीमनाबाद तक फैला दिया। रीवा राज्य के कुछ अधिकारियों ने अंग्रेज़ों से मिलकर रणमत सिंह से विश्वासघात कर उन्हें पकड़वा दिया। ब्रिटिश सेना ने उन्हें पकड़कर बाँदा जेल भेद दिया, जहाँ अगस्त 1859 में उन्हें फाँसी पर चढ़ा दिया गया।
चंद्रशेखर आज़ाद	23 जुलाई, 1906 को चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म अलीराजपुर ज़िले के भाबरा ग्राम में हुआ था। 27 फरवरी, 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में इनकी पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई जिसमें वह आखिरी गोली खुद को मारकर शहीद हो गए।
गुलाब सिंह पटेल	महाकौशल क्षेत्र के वीर गुलाब सिंह पटेल का नाम मध्य प्रदेश के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में लिया जाता है। गुलाब सिंह के नेतृत्व में अगस्त 1942 में गिरफ्तार किये गए कांग्रेस नेताओं के विरोध में जबलपुर में एक आंदोलन चलाया गया। आंदोलन में पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किये जाने के परिणामस्वरूप गुलाब सिंह शहीद हो गए। इस घटना ने संस्कारधानी सहित पूरे महाकौशल क्षेत्र में 'करो या मरो' की भावना को और प्रबल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।

परीक्षोपयोगी महत्त्वपूर्ण तथ्य

- राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष बना रहा क्योंकि भारत के प्रत्येक धर्म के अनुयायियों ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी।
- उदारवादी नेता रमेशचंद्र दत्त ने भारत के आर्थिक इतिहास पर प्रथम पुस्तक 'Economic History of India' की रचना की।
- प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक एम. विश्वेश्वरैया हैं। इन्हें भारत की योजना का जनक कहा जाता है।
- उदारवादियों के प्रयास से 1886 ई. में भारत और इंग्लैंड में एक साथ सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन तथा भारतीय व्यय की समीक्षा हेतु 1895 में **वैल्वी आयोग** का गठन हुआ।
- प्रथम चरण के उदारवादी नेता दादाभाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत प्रस्तुत किया तथा लोगों के सामने ब्रिटिश सरकार द्वारा किये जाने वाले आर्थिक शोषण का एक ब्योरा रखा।
- भारत में उग्रवाद आंदोलन का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को दिया जाता है, उन्होंने ही गणपति महोत्सव तथा शिवाजी महोत्सव के माध्यम से लोगों में राष्ट्रवादी भावना का प्रसार किया।
- 'स्वराज' का नारा सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने ही दिया परंतु कांग्रेस के मंच से इसकी मांग दादाभाई नौरोजी के द्वारा की गई।

- बंगाल में प्रथम क्रांतिकारी संगठन **अनुशीलन समिति** थी, जिसकी स्थापना 1902 ई. में मिदनापुर में ज्ञानेंद्र बसु द्वारा तथा कलकत्ता में जतींद्रनाथ बनर्जी और बारींद्रनाथ घोष द्वारा की गई।
- भारत से बाहर अन्य देशों में स्थापित पुरानी संस्था इंडिया होमरूल सोसाइटी थी, जिसकी स्थापना **श्यामजी कृष्ण वर्मा** ने लंदन में 1905 ई. में की थी।
- मुस्लिम लीग के 1913 ई. के लखनऊ अधिवेशन में पहली बार मुहम्मद अली जिन्ना ने भाग लिया तथा लीग के नेताओं ने स्वशासन को राष्ट्रीय लक्ष्य स्वीकार किया और कॉंग्रेस के साथ सहयोग पर बल दिया।
- मॉन्टेग्यू घोषणा (1917 ई.) को उदारवादियों ने भारत के मैग्नाकार्टा की संज्ञा दी। मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के आधार पर ही भारत सरकार अधिनियम, 1919 निर्मित हुआ।
- 1918 ई. में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में कॉंग्रेस के उदारवादी नेताओं ने मॉन्टेग्यू सुधारों का स्वागत किया तथा कॉंग्रेस से अलग होकर **अखिल भारतीय उदारवादी संघ** की स्थापना की।
- राजकुमार शुक्ल बिहार के चंपारण ज़िले (वर्तमान में पश्चिमी चंपारण ज़िला) के कृषक और स्वतंत्रता सेनानी थे। शुक्ल चंपारण में तिनकठिया प्रथा को लेकर काफी व्यथित थे और उनके आमंत्रण पर ही गांधी जी चंपारण गए और नील की फसल के लिये लागू तिनकठिया प्रथा के विरोध में चंपारण में सत्याग्रह का पहला सफल प्रयोग किया।
- महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के बाद ही रवींद्रनाथ टैगोर ने उन्हें पहली बार **महात्मा** की उपाधि दी।
- महात्मा गांधी ने दिसंबर 1924 में बेलगाम (कर्नाटक) में कॉंग्रेस के एकमात्र वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। साथ ही 1937 में 'अखिल भारतीय हरिजन संघ' की स्थापना भी की।
- 'पब्लिक सेफ्टी बिल' को मोतीलाल नेहरू ने भारतीय गुलामी विधेयक न. 1 की संज्ञा की दी।
- सुभाष चंद्र बोस ने भगत सिंह के बारे में कहा था, "भगत सिंह ज़िंदाबाद और इनकलाब ज़िंदाबाद का एक ही अर्थ है।"
- भारत छोड़ो आंदोलन (1942 ई.) के समय ही गांधीजी को अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी और निजी सचिव महादेव देसाई के देहांत की सूचना मिली।
- भारत छोड़ो आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम ऐसा आंदोलन था जो पूरी तरह **नेतृत्वविहीन** था, इसी आंदोलन ने **करो या मरो (Do or Die)** का नारा दिया।
- भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था।
- महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्तावों पर टिप्पणी की थी कि यह **उत्तरतिथीय चेक** (Post-Dated Cheque) है तथा किसी और ने संभवतः जवाहरलाल नेहरू ने इसमें यह जोड़ दिया कि 'ऐसे बैंक के नाम, जो टूट रहा है'।
- **विनायक दामोदर सावरकर** ने 1904 ई. में **अभिनव भारत समाज** नामक संस्था की स्थापना की थी।
- **बी.आर. अबेडकर** ने दलितों का प्रतिनिधि करने के लिये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था।
- आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय **रंगून** में स्थित था।

बहुविकल्पीय प्रश्न

- | | |
|--|--|
| 1. 'भारत छोड़ो' का नारा किसने दिया था?
M.P.P.C.S. (Pre) 2018 | 3. इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था?
M.P.P.C.S. (Pre) 2017 |
| (a) महात्मा गांधी (b) जवाहरलाल नेहरू | (a) महादेव देसाई (b) प्यारेलाल नैयर |
| (c) यूसुफ मेहर अली (d) अरुणा आसफ अली | (c) मदनमोहन मालवीय (d) जवाहरलाल नेहरू |
| 2. 'प्लांड इकोनॉमी फॉर इंडिया' पुस्तक के लेखक कौन हैं?
M.P.P.C.S. (Pre) 2018 | 4. चटगाँव अमरी रेड से इनमें से कौन संबंधित था?
M.P.P.C.S. (Pre) 2016 |
| (a) एम. विश्वेश्वरैया (b) जे.आर.डी. टाटा | (a) सूर्य सेन (b) भगत सिंह |
| (c) जी.डी. बिरला (d) पट्टाभि सीतारमैया | (c) रामप्रसाद बिस्मिल (d) अशफाक उल्लाह |

5. वेवेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी?
M.P.P.C.S. (Pre) 2016
(a) 1942 ई. (b) 1943 ई.
(c) 1944 ई. (d) 1945 ई.
6. अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
M.P.P.C.S. (Pre) 2014
(a) 1905 ई. (b) 1904 ई.
(c) 1907 ई. (d) 1906 ई.
7. 1938 ई. के लिये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था?
M.P.P.C.S. (Pre) 2014
(a) जवाहरलाल नेहरू
(b) सुभाष चंद्र बोस
(c) अबुल कलाम आज़ाद
(d) वल्लभभाई पटेल
8. भारत के विभाजन से संबंधित 'माउंटबेटन योजना' की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी?
M.P.P.C.S. (Pre) 2014
(a) 4 जून, 1947 (b) 10 जून, 1947
(c) 3 जुलाई, 1947 (d) 3 जून, 1947
9. निम्नलिखित में से किसने 'गदर पार्टी' का गठन किया?
M.P.P.C.S. (Pre) 2013
(a) वी.डी. सावरकर (b) रासबिहारी बोस
(c) मदनलाल दींगरा (d) लाला हरदयाल
10. 'आज़ाद हिंद फौज' का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित था?
M.P.P.C.S. (Pre) 2013
(a) टोकियो (b) रंगून
(c) बर्लिन (d) दिल्ली
11. निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध 'आई.एन.ए. मुकदमे' के वकील थे?
M.P.P.C.S. (Pre) 2012
(a) सुभाष चंद्र बोस (b) सी. राजगोपालाचारी
(c) आसफ अली (d) भूलाभाई देसाई
12. निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज़ सम्मेलनों में भाग लिया था?
M.P.P.C.S. (Pre) 2012
(a) वल्लभभाई पटेल
(b) मदनमोहन मालवीय
(c) बी.आर. अंबेडकर
(d) उपर्युक्त में से किसी ने नहीं
13. निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के संगठन 'अभिनव भारत' को संगठित किया था?
(a) जतींद्रनाथ मुखर्जी
(b) मदनलाल दींगरा
(c) विनायक दामोदर सावरकर
(d) लाला हरदयाल
14. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था?
(a) 1917 ई. (b) 1918 ई.
(c) 1920 ई. (d) 1924 ई.
15. राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान घटित चौरी-चौरा कांड का संबंध निम्नलिखित में किस आंदोलन से है?
(a) स्वदेशी आंदोलन
(b) असहयोग आंदोलन
(c) सविनय अवज्ञा आंदोलन
(d) भारत छोड़ो आंदोलन
16. स्वराज पार्टी को संस्थापित किया था—
(a) बाल गंगाधर तिलक तथा लाला लाजपत राय
(b) महात्मा गांधी तथा मोतीलाल नेहरू
(c) वल्लभभाई पटेल तथा जवाहरलाल नेहरू
(d) मोतीलाल नेहरू तथा सी.आर. दास
17. 1927 ई. में गठित साइमन आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था?
(a) भारत में संवैधानिक सुधार पर विचार करना
(b) शिक्षा में सुधार करना
(c) कृषि क्षेत्र में सुधार करना
(d) सैनिक क्षमता का मूल्यांकन करना
18. कांग्रेस ने 1929 ई. के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य 'पूर्ण स्वराज' घोषित किया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी?
(a) महात्मा गांधी (b) जवाहरलाल नेहरू
(c) सुभाष चंद्र बोस (d) मोतीलाल नेहरू
19. ऐतिहासिक 'दांडी मार्च' का संबंध किस घटना से है?
(a) चुनाव बहिष्कार
(b) नमक कानून तोड़ने से
(c) अस्पृश्यता उन्मूलन से
(d) हिंदू-मुस्लिम एकता से

20. महात्मा गांधी धरसाना नमक गोदाम पर कॉन्ग्रेस कार्यकर्ताओं के हमले के समय कहाँ थे?
 (a) यरवदा जेल में (b) साबरमती जेल में
 (c) अहमदनगर जेल में (d) आगा खाँ पैलेस पूना में
21. निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी-इर्विन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था?
 (a) असहयोग आंदोलन (b) खिलाफत आंदोलन
 (c) गोलमेज़ सम्मेलन (d) सविनय अवज्ञा आंदोलन
22. अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी?
 (a) महात्मा गांधी (b) डॉ. भीमराव अंबेडकर
 (c) नारायण गुरु (d) जवाहरलाल नेहरू
23. बी.आर. अंबेडकर तथा महात्मा गांधी के मध्य एक समझौता हुआ, जो कहलाता है—
 (a) लंदन समझौता (b) लखनऊ समझौता
 (c) पूना समझौता (d) दिल्ली समझौता
24. प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में किस अधिनियम के तहत किया गया था?
 (a) 1935 का अधिनियम (b) 1937 का अधिनियम
 (c) 1919 का अधिनियम (d) 1942 का अधिनियम
25. सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस का अध्यक्ष कौन बना?
 (a) राजेंद्र प्रसाद
 (b) वल्लभभाई पटेल
 (c) अबुल कलाम आज़ाद
 (d) जवाहरलाल नेहरू
26. सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस का अध्यक्ष कितनी बार बने?
 (a) एक बार (b) दो बार
 (c) तीन बार (d) चार बार
27. 1937 ई. में प्रांतों में सरकार निर्माण के उपरांत कॉन्ग्रेस का शासन कितने माह तक चला?
 (a) 26 माह (b) 28 माह
 (c) 30 माह (d) 32 माह

उत्तरमाला

1. (c) 2. (a) 3. (d) 4. (a) 5. (d) 6. (d) 7. (b) 8. (d) 9. (d) 10. (b)
 11. (d) 12. (c) 13. (c) 14. (c) 15. (b) 16. (d) 17. (a) 18. (b) 19. (b) 20. (a)
 21. (d) 22. (a) 23. (c) 24. (a) 25. (a) 26. (b) 27. (b)

अति लघुउत्तरीय प्रश्न (उत्तर 10-20 शब्दों/एक-दो पंक्तियों में दीजिये)

- राजकुमार शुक्ल
- चौरी-चौरा घटना
- जलियाँवाला बाग हत्याकांड
- गोपाल कृष्ण गोखले
- मुस्लिम लीग
- एनी बेसेंट
- दांडी मार्च
- क्रिप्स मिशन
- पूना पैक्ट
- भारत छोड़ो आंदोलन
- काकोरी कांड

M.P.P.C.S. (Mains) 2018
 M.P.P.C.S. (Mains) 2017
 M.P.P.C.S. (Mains) 2016
 M.P.P.C.S. (Mains) 2015
 M.P.P.C.S. (Mains) 2015
 M.P.P.C.S. (Mains) 2015
 M.P.P.C.S. (Mains) 2015
 M.P.P.C.S. (Mains) 2015
 M.P.P.C.S. (Mains) 2015
 M.P.P.C.S. (Mains) 2014
 M.P.P.C.S. (Mains) 2014

लघुउत्तरीय प्रश्न (उत्तर 50 शब्दों या 5 से 6 पंक्तियों में दीजिये)

- वेवेल योजना
- कैबिनेट मिशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये।

3. नेहरू रिपोर्ट क्या है?
4. लाहौर अधिवेशन कब हुआ?
5. मुस्लिम लीग की पाकिस्तान मांग पर चर्चा कीजिये।
6. लखनऊ समझौता के बारे में बताइये।

दीर्घउत्तरीय प्रश्न (उत्तर लगभग 100/200/300 शब्दों में दीजिये)

1. मध्य प्रदेश के झंडा सत्याग्रह आंदोलन पर प्रकाश डालिये। (300 शब्द) M.P.P.C.S. (Mains) 2018
2. उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिये जिनमें भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। (100 शब्द) M.P.P.C.S. (Mains) 2017
3. गांधीजी ने देश के विभाजन को क्यों स्वीकार किया? (100 शब्द) M.P.P.C.S. (Mains) 2017
4. जबलपुर झंडा सत्याग्रह (1923) पर प्रकाश डालिये। (100 शब्द) M.P.P.C.S. (Mains) 2016
5. स्वराज पार्टी पर एक संक्षिप्त लेख लिखें। (100 शब्द) M.P.P.C.S. (Mains) 2016
6. उदारवादियों (1885-1905) का मूल्यांकन कीजिये। (100 शब्द) M.P.P.C.S. (Mains) 2016
7. कॉंग्रेस ने देश विभाजन को क्यों स्वीकार कर लिया? समझाकर लिखिये। (100 शब्द) M.P.P.C.S. (Mains) 2016
8. सूरत की फूट पर एक टिप्पणी लिखिये। (100 शब्द) M.P.P.C.S. (Mains) 2015
9. गांधी-इर्विन समझौते का संक्षिप्त वर्णन कीजिये। (100 शब्द) M.P.P.C.S. (Mains) 2015
10. भारत की स्वतंत्रता में सहायक तत्वों का वर्णन कीजिये। (100 शब्द) M.P.P.C.S. (Mains) 2014
11. असहयोग आंदोलन ने कॉंग्रेस के आधार को किस प्रकार विस्तारित किया? स्पष्ट कीजिये।
12. सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं? संक्षिप्त परिचय दीजिये।
13. होमरूल आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं? स्पष्ट कीजिये।
14. आजाद हिंद फौज पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये।

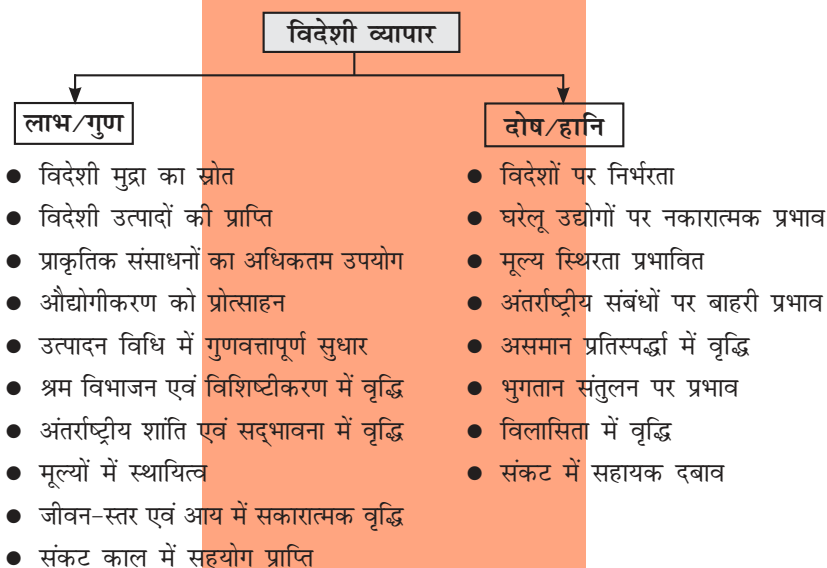
वैश्वीकरण के दौर में विश्व व्यापार एक अपरिहार्य आवश्यकता है। वैश्विक व्यापार में वृद्धि होने से अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक निर्भरता भी निरंतर बढ़ रही है। विदेशी व्यापार का अर्थ दो या दो से अधिक देशों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं का व्यापार है। किसी भी देश के विदेशी व्यापार में उसके आयात और निर्यात दोनों घटकों को शामिल किया जाता है। कोई भी देश उत्पादन एवं उपभोग क्षेत्र में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं होता है इसलिये विदेशी व्यापार अत्यंत महत्वपूर्ण है।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेशी व्यापार के बिना देश अपनी घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं तक सीमित रह जाएंगे। इसी कमी को दूर करने के लिये विदेशी व्यापार की आवश्यकता का जन्म हुआ है। विदेशी व्यापार को विश्व व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी कहते हैं। विदेशी व्यापार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पारस्परिक सहयोग से एक-दूसरे पर निर्भरता तथा एक-दूसरे की भागीदारी एवं सहायता से आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है।

10.1 विदेशी व्यापार : सामान्य परिचय (Foreign Trade : General Introduction)

“दो राष्ट्रों के मध्य वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रय-विक्रय को विदेशी व्यापार कहते हैं।” किसी देश के विदेशी व्यापार से उसकी अर्थव्यवस्था की प्रकृति और उसके आकार का पता चलता है। विदेशी व्यापार किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्रिया में श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण द्वारा उत्पादन साधनों की दक्षता और कार्य कुशलता में वृद्धि कर आर्थिक उन्नयन करता है। खुली अर्थव्यवस्था को विदेशी व्यापार प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। विदेशी व्यापार की महत्ता वैश्वीकरण के इस दौर में बहुत अधिक बढ़ गई है। किसी भी देश के लिये विदेशी व्यापार का महत्त्व निम्नलिखित रूप में है-

1. यह विदेशी मुद्रा अर्जन का प्रमुख साधन है।
2. विभिन्न देशों के मध्य पारस्परिक सहयोग में वृद्धि करता है।
3. आवश्यक वस्तुओं के आयात तथा अधिशेष वस्तुओं के निर्यात से अर्थव्यवस्था में संतुलन स्थापित होता है।
4. बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करता है।
5. मशीनरी, तकनीक एवं पूंजीगत आयात से अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक मजबूती आती है।
6. विदेशी व्यापार किसी भी राष्ट्र की उन्नति का महत्वपूर्ण कारक है।



किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास एवं संवृद्धि में उस राष्ट्र के आंतरिक एवं बाह्य व्यापार का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। किसी भी राष्ट्र की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति आंतरिक साधनों एवं क्रियाओं के द्वारा नहीं की जा सकती, इसलिये बाह्य या विदेशी व्यापार को अनुकूल रखे जाने पर अधिक ध्यान दिया जाता है। देश की आर्थिक प्रगति के लिये निर्यात बढ़ाने एवं आयात निर्भरता कम करने का निरंतर प्रयास किया जाता है। निर्यात में वृद्धि भुगतान संतुलन एवं विदेशी विनिमय कोष के लिये भी आवश्यक है। किसी भी देश के विदेशी लेन-देन का पूर्ण विवरण भुगतान संतुलन के माध्यम से ज्ञात होता है। भुगतान संतुलन किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को चालू खाते एवं पूंजीगत खातों के माध्यम से प्रस्तुत करता है।

11.1 भुगतान संतुलन : अर्थ एवं अवधारणा (Balance of Payment : Meaning and Concepts)

किसी देश का भुगतान संतुलन एक निश्चित अवधि सामान्यतः एक वित्तीय वर्ष में उस देश और शेष विश्व के साथ उसके सभी व्यापार, जिनके मौद्रिक मूल्य की गणना हो सकती है, का क्रमबद्ध विवरण होता है। दूसरे शब्दों में भुगतान संतुलन खाते इस प्रकार के खाते होते हैं, जिनमें किसी अर्थव्यवस्था अथवा देश का शेष विश्व के साथ सभी प्रकार के मौद्रिक लेन-देन (Monetary Transactions) का लेखांकन दर्ज किया जाता है। इसमें सभी प्रकार के आर्थिक लेन-देन (दृश्य, अदृश्य या पूंजीगत) का समस्त विवरण उपलब्ध होता है।

कोई देश जब विश्व के अन्य देशों को वस्तु एवं सेवाएँ विक्रय करता है तो उसे निर्यात कहते हैं तथा दूसरे देशों से जिन वस्तु एवं सेवाओं का क्रय करता है उसे हम उसका आयात कहते हैं। आयात-निर्यात के दौरान दृश्य मदों एवं अदृश्य मदों के तहत प्रविष्टि की जाती है। दृश्य मदों के अंतर्गत वस्तुओं के आदान-प्रदान तथा अदृश्य मदों के अंतर्गत सेवाओं (पर्यटन, चिकित्सा, कंसल्टेंसी, सॉफ्टवेयर, शिक्षा) के आदान-प्रदान को सम्मिलित किया जाता है। पूंजी खाते के अंतर्गत बैंकिंग जमा, विदेशी ऋण, विदेशी निवेश, आप्रवासियों और एन.आर.आई. जमा आदि को सम्मिलित किया जाता है।

चालू खाता (Current Account)	व्यापार खाता (Trade Account)	1. निर्यात (Export – X) 2. आयात (Import – M) 3. व्यापार शेष (Balance of Trade or X – M)
	अदृश्य खाता (Invisible Account)	4. अदृश्य शेष (Invisible Balance) (क) कारक सेवा व्यापार शेष (Factor service Balance of Trade) (i) निजी अंतरण/प्रेषण (Private Transfer/Remittance) (ii) निवेश आय (Investment Income) (ख) गैर-कारक सेवा व्यापार शेष (Non-Factor Service Balance of Trade)
	वस्तु एवं सेवा खाता (Goods and Service Account)	5. वस्तु एवं सेवा शेष (3 + 4 ख) (Goods and Service Balance)
	चालू खाता (Current Account)	6. चालू शेष (3 + 4 क + 4 ख) (Current Balance)

अंतर्राष्ट्रीय संगठन (International Organisation)

‘अंतर्राष्ट्रीय संगठन’ पद का प्रयोग सर्वप्रथम स्कॉटलैंड के प्रमुख विधिवेत्ता जेम्स लोरिमेर ने किया था। अंतर्राष्ट्रीय संगठन उन संस्थाओं को कहते हैं जिनके सदस्य, कार्यक्षेत्र, प्रकृति, भूमिका एवं विस्तार वैश्विक स्तर पर हो। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आधारशिला अपने हितों की रक्षा के लिये विभिन्न राज्यों के मध्य स्वेच्छापूर्ण तरीके के स्वीकार्य अनुशासन एवं नियंत्रण की आवश्यकता ने रखी। विभिन्न देशों द्वारा अपनी समस्याओं तथा अन्य वैश्विक विवादों पर साझा विचार-विमर्श के माध्यम से सहमति एवं समाधान प्राप्त करने तथा पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निष्पक्ष एवं तटस्थ मंच की स्थापना की आवश्यकता ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को जन्म दिया। ये संगठन विभिन्न राष्ट्रों की संप्रभुता की रक्षा करते हुए शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, सहयोग एवं स्पृद्धा बनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में कई प्रकार की श्रेणियों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन कार्यरत हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा एवं सहयोग के लिये संयुक्त राष्ट्र संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

इसी संदर्भ में देखें तो, वैश्विक स्तर पर पूंजी एवं तकनीकी के लेन-देन के माध्यम से संतुलित एवं समन्वित आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई विकास बैंक तथा विश्व व्यापार संगठन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा क्षेत्रीय स्तर पर व्यापार एवं सहयोग को बढ़ावा देने के लिये मुक्त व्यापार समझौतों के क्रियान्वयन से आसियान, सार्क, शंघाई सहयोग संगठन, एपेक, यूरोपीय यूनियन आदि जैसे संगठन भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

12.1 संयुक्त राष्ट्र संघ (United Nations Organisation)

क्या यह एक विचित्र संयोग है कि मानव आचरण में युद्ध एवं शांति, विध्वंस एवं निर्माण के बीज एक साथ निहित दिखाई देते हैं जैसा कि नेपोलियन युद्धों के बाद हॉली एलायंस (Holy Alliance), प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात् राष्ट्र संघ की स्थापना एवं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना इसके प्रमाण के रूप में दिखाई देते हैं।

प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात् राष्ट्र संघ की स्थापना में जहाँ अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने प्रमुख भूमिका निभाई थी वहीं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैसी ही भूमिका एक अन्य अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट की थी।

संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर, 1945 को संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर करने के साथ हुई। दो विश्व युद्धों की विभीषिका एवं राष्ट्र संघ की असफलता के बाद अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा एवं सहयोग की आवश्यकता ने संयुक्त राष्ट्र संघ को जन्म दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क (संयुक्त राज्य अमेरिका) में है और इसके वर्तमान सदस्यों की संख्या 193 है। 24 अक्टूबर को हर वर्ष ‘संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस’ के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान में इसके महासचिव एंटोनियो गुटेरेस (पुर्तगाल) हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य (Objectives of UNO)

संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 1 के अनुसार इसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं—

- अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना।
- समान अधिकार और लोगों को आत्म-निर्णय सिद्धांत के आधार पर देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करना।
- अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मानवीय समस्याओं के समाधान के लिये सहयोग करना और मानवाधिकारों एवं बुनियादी स्वतंत्रता के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना।
- इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये प्रयास कर रहे देशों की गतिविधि में समन्वय स्थापित करने के लिये एक केंद्र के रूप में कार्य करना।

समय के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ ने इन उद्देश्यों से जुड़े हुए लक्ष्य भी निर्धारित किये हैं, ये हैं— निरस्त्रीकरण और नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करना।

“आदर्श समाज गतिशील होना चाहिये, उसमें एक भाग में हो रहे परिवर्तन को दूसरे भाग तक पहुँचाने के भरपूर माध्यम होने चाहिये।”

—डॉ. बी.आर. अंबेडकर

विकास परिवर्तन की एक ऐसी सतत् प्रक्रिया है, जो लोगों को इस योग्य बनाती है कि वे सक्षम एवं सृजनात्मक बन सकें। विकास सकारात्मक परिवर्तन को ईगित करता है। पिछड़ेपन के साथ मानव विकास संभव नहीं है इसलिये विकास योजनाएँ मानव विकास तथा उच्चतम जीवन स्तर प्राप्त करने के लिये लक्ष्य करके बनाई जाती हैं। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास कार्यक्रम की ओर से प्रतिवर्ष मानव विकास रिपोर्ट जारी की जाती है जिसमें जीवन-स्तर, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक समानता आदि मानकों को विकास का प्रमुख वाहक माना जाता है। विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रयास करती है। इस रूप में नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार नीति प्रतिपादन किया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के समग्र विकास को आगे बढ़ाने में नगरीय एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों की महत्वपूर्ण एवं समान भूमिका है। चूँकि विकास का प्रमुख वाहक आधारभूत संरचना को माना जाता है इसलिये आधारभूत संरचना या अवसंरचना के विकास पर प्रमुख रूप से ध्यान दिया जाता है। अवसंरचना विकास समावेशी विकास, आर्थिक संवृद्धि, निर्धनता कम करने तथा वृहत् विकास लक्ष्यों को पाने के लिये बहुत महत्वपूर्ण है।

13.1 अवसंरचना (Infrastructure)

किसी भी अर्थव्यवस्था के सुचारु रूप से कार्य करने, विकास करने एवं प्रगति के लिये जिन सुविधाओं, क्रियाओं व सेवाओं की आवश्यकता होती है, उसे अवसंरचना, अधोसंरचना या आधारभूत संरचना कहा जाता है। अवसंरचना आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों के मूल तत्त्व को प्रकट करती है तथा सहयोगी व्यवस्था का कार्य करती है, जैसे-सड़क, बिजली, परिवहन, संचार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य की व्यवस्था, ऊर्जा आदि।

अवसंरचना या आधारभूत संरचना को दो भागों में विभाजित किया जाता है-

(1) आर्थिक अवसंरचना (Economic Infrastructure)

इसके अंतर्गत उन सभी तत्त्वों को सम्मिलित किया जाता है जो आर्थिक गतिविधियों की रीढ़ हैं एवं उनकी वृद्धि में सहायक होते हैं। आर्थिक विकास की बुनियादी आवश्यकता के घटकों को आर्थिक अवसंरचना कहा जाता है। इसमें शक्ति, परिवहन, दूरसंचार आदि को सम्मिलित किया जाता है।

(2) सामाजिक अवसंरचना (Social Infrastructure)

इसके अंतर्गत उन सभी तत्त्वों को सम्मिलित किया जाता है जो सामाजिक गतिविधियों के विस्तार एवं विकास में सहायक हैं तथा सहयोगी भूमिका निभाते हैं। ये मानव संसाधन विकास और मानव पूंजी निर्माण में सहायक हैं। समाज को कुशल, निपुण एवं स्वस्थ मानव संसाधन उपलब्ध कराने वाली अवसंरचना को सामाजिक अवसंरचना कहा जाता है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास आदि को शामिल किया जाता है।

अवसंरचना की भूमिका (Role of infrastructure)

देश के आर्थिक विकास एवं प्रगति में अवसंरचना की महत्वपूर्ण भूमिका है। आर्थिक एवं सामाजिक अवसंरचनाएँ एक-दूसरे की पूरक हैं। सामाजिक अवसंरचनात्मक ढाँचे के बिना आर्थिक अवसंरचनात्मक ढाँचे का कोई अर्थ नहीं है तथा आर्थिक अवसंरचनात्मक ढाँचे के बिना सामाजिक अवसंरचनात्मक ढाँचा औचित्यहीन है। इसलिये सामाजिक एवं आर्थिक अवसंरचना का संयुक्त विकास आवश्यक है। ये निम्नलिखित भूमिका निभाती हैं-

आधुनिक काल में सहकारिता की आवश्यकता एवं महत्त्व बहुत अधिक है। यह शांतिपूर्ण तरीके से तृणमूल स्तर पर सामाजिक परिवर्तन लाने और एक शोषण रहित एवं समानता आधारित सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करने का प्रमुख साधन है। सहकारिता एक ऐसा स्वेच्छापूर्ण संगठन है जो लोकतंत्र, समानता व आत्म-सहायता के आधार पर निजी हित एवं संपूर्ण समुदाय के हित के लिए कार्य करता है। सहकारिता एक सामाजिक-आर्थिक आंदोलन है जो परस्पर सामंजस्य पर आधारित प्रयास में विश्वास करता है।

आर्थिक विकास की गति को तीव्रता प्रदान करने में सहकारिता आंदोलन का विशेष महत्त्व रहा है। सहकारी समितियों का समाज में इतना अधिक महत्त्व इसलिए है क्योंकि यह संगठन शोषण रहित सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करने में सहायक है। सहकारी समितियों का उद्देश्य न्यूनतम लागत पर अधिकतम सुविधाएँ व्यापक जनहित में उपलब्ध कराना होता है।

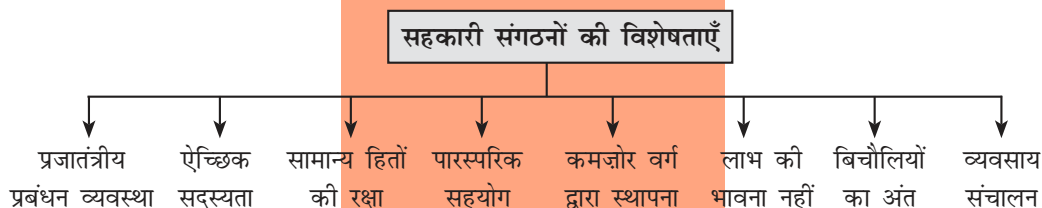
14.1 सहकारिता : सामान्य परिचय (Co-operative : General Introduction)

सहकारिता का अर्थ (Meaning of Co-operative)

एच. डैलबर्ट— “सहकारिता एक ऐसा संगठन है जिसमें व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक मानवतापूर्ण ढंग से समानता के आधार पर अपने आर्थिक हितों को पूरा करने के लिए संगठित होते हैं।” सहकारिता शब्द ‘सह+कारिता’ के योग की निर्मिति है जहाँ ‘सह’ का अर्थ है— ‘मिल-जुलकर या साथ-साथ तथा ‘कारिता’ का अर्थ है— कार्य करना। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि सहकारिता एक ऐसा संगठन है जिसमें समानता को आधार बनाकर पारस्परिक हितों को ध्यान में रखकर एक साथ मिल-जुलकर काम किया जाता है। सहकारिता ‘एक सबके लिये और सब एक के लिये’ की अवधारणा पर अवलंबित है। सहकारिता आत्म-सहायता, स्व-उत्तरदायित्व, लोकतंत्र, समानता, समता और एकजुटता के मूल्यों पर आधारित है।

सहकारी संगठनों की विशेषताएँ (Characteristics of co-operative organizations)

सहकारिता एक ऐसा संगठन है जिसमें मनुष्य समानता के आधार पर अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये सहयोग करते हैं। इसकी विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—



- **प्रजातंत्रीय प्रबंधन व्यवस्था** : इसमें सभी सदस्यों द्वारा चुनी हुई समिति प्रबंधन कार्य करती है। ‘एक व्यक्ति एक मत’ का सिद्धांत लागू होता है चाहे व्यक्ति के पास कितना ही अंश क्यों न हो।
- **ऐच्छिक सदस्यता** : इसमें व्यक्ति स्वेच्छा से शामिल होते हैं। इसके सदस्य बनने हेतु समिति में अंशदान करना होता है। इसके सदस्य जब चाहे इससे अलग हो सकते हैं।

एक कल्याणकारी राष्ट्र में गरीबों एवं वंचित वर्गों के गरिमापूर्ण जीवन के लिये सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएँ चलाई जाती हैं। योजनाओं के माध्यम से सरकार आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय एवं आर्थिक संवृद्धि सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। इसी संदर्भ में केंद्र एवं मध्य प्रदेश सरकार की कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं का वर्णन यहाँ किया जा रहा है।

15.1 केंद्र सरकार की योजनाएँ (Central Government's Schemes)

एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड योजना

- केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution) ने 30 जून, 2020 तक पूरे देश में 'एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड' योजना लागू करने की घोषणा की है।
- इस योजना के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आने वाले लाभार्थी (विशेषकर प्रवासी) देश के किसी भी भाग में, खाद्यान्न प्राप्त करने में सक्षम हो पाएंगे।
- इसके माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का ही फायदा लिया जा सकेगा। यदि कोई राज्य अपने स्तर पर अपने नागरिकों के लिये किसी प्रकार की खाद्य सुरक्षा योजना चला रहा है तो अन्य राज्य के नागरिक इसका फायदा नहीं ले पाएंगे।
- वर्तमान में आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा ऐसे 10 राज्य हैं, जहाँ खाद्यान्न वितरण का 100 प्रतिशत कार्य प्वाइंट ऑफ सेल (POS) मशीनों के जरिये हो रहा है।
- इन राज्यों में सार्वजनिक वितरण की सभी दुकानों को इंटरनेट से जोड़ा जा चुका है तथा यहाँ लाभार्थी सार्वजनिक वितरण की किसी भी दुकान से अनाज प्राप्त कर सकते हैं।
- सभी सार्वजनिक वितरण प्रणालियों को डिपो ऑनलाइन प्रणाली (DOS) के साथ जोड़ा जा रहा है, ताकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभों को लोगों तक पहुँचाने में कोई अवरोध न हो।

किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (KUSUM)

- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति (Cabinet Committee on Economic Affairs-CCEA) ने किसानों को वित्तीय और जल सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान-कुसुम (Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahabhiyan-KUSUM) को शुरू करने की मंजूरी दे दी है।
- तीनों घटकों को शामिल करने वाली इस योजना का लक्ष्य वर्ष 2022 तक कुल 25,750 मेगावाट की सौर क्षमता स्थापित करना है।
- इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार 34,422 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
- राज्य सरकार 30 प्रतिशत की सब्सिडी देगी और शेष 40 प्रतिशत खर्च का वहन किसानों को करना होगा। लागत के 30 प्रतिशत खर्च के लिये बैंकों से सहायता भी प्राप्त की जा सकती है। शेष 10 प्रतिशत लागत किसान के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
- इस योजना से ग्रामीण भू-स्वामियों को स्थायी व निरंतर आय का स्रोत प्राप्त होगा।
- किसान उत्पादित ऊर्जा का उपयोग सिंचाई जरूरतों के लिये कर पाएंगे तथा अतिरिक्त ऊर्जा बिजली वितरण कंपनियों को बेच पाएंगे। इससे किसानों को अतिरिक्त आय प्राप्त होगी।

योजना के घटक

- घटक A : भूमि के ऊपर बनाए गए 10,000 मेगावाट के विकेंद्रीकृत ग्रिडों को नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों से जोड़ना।
- घटक B : 17.50 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना।
- घटक C : ग्रिड से जुड़े 10 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों का सौरिकरण (Solarisation)

- **आर्बिट्रेज (Arbitrage) :** विभिन्न विदेशी मुद्राओं को एक साथ इस उद्देश्य से खरीदना और बेचना जिससे विश्व के विभिन्न बाजारों में विदेशी विनिमय दरों में पाए जाने वाले अंतर से लाभ उठाया जा सके, आर्बिट्रेज कहलाता है।
- **एन्युटी (Annuity) :** किसी एक पूर्व निर्धारित योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष एक या अधिक किस्तों में होने वाला भुगतान एन्युटी कहलाता है, जैसे- सरकारी ऋणपत्रों पर ब्याज का भुगतान।
- **एडवांस डिक्लाइन (Advance decline) :** यह शेयर बाजार की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करने वाला एक माप है। किसी समयावधि में मूल्य वृद्धि को प्रदर्शित करने वाले शेयरों की संख्या का मूल्य ह्रास वाले शेयरों की संख्या के साथ अनुपात ही एडवांस डिक्लाइन कहलाता है।
- **एयर पॉकेट (Air pocket) :** यदि किसी कंपनी के शेयरों के पहले दिन के बंद भाव तथा दूसरे दिन के खुलने वाले भाव में काफी अंतर होता है तो वह स्थिति एयर पॉकेट की होती है। यह कई कारणों से घटित होता है। जैसे कि यदि किसी कंपनी के विषय में कोई प्रतिकूल सूचना आती है तो कंपनी के शेयरों के भाव गिर जाते हैं। शेयरों के भाव में उतार-चढ़ाव की स्थिति का होना सामान्य बात है।
- **अग्रिम कर (Advance tax) :** अग्रिम कर प्रत्येक वर्ष मार्च, सितंबर एवं दिसंबर में देय होता है ताकि प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व ही आगामी वित्तीय वर्ष के बजट के संबंध में अपनी राजस्व प्राप्तियों से अवगत हो सके। अग्रिम कर अर्जित आय के आधार पर देय सिद्धांत पर आधारित है।
- **बिटकॉइन (Bitcoin) :** यह समान समूह और जान-पहचान वाले लोगों के बीच इलेक्ट्रॉनिक मनी और पेमेंट नेटवर्क का खुला माध्यम है।
- **आधार प्रभाव (Base effect) :** वर्तमान आँकड़ों की गणना पर पहले के आँकड़ों का पड़ने वाला प्रभाव 'आधार प्रभाव' कहलाता है। स्फीति दर में वृद्धि के संदर्भ में वर्तमान स्फीति दर की गणना पर विगत वर्षों की कीमतों का पड़ने वाला प्रभाव आधार प्रभाव कहलाता है।
- **बूम (Boom) :** अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं की तेजी से विस्तार की स्थिति को बूम कहा जाता है। यह स्थिति मंदी के विपरीत है। मांग में वृद्धि के कारण ही किसी उद्योग विशेष में बूम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
- **काला बाजार (Black market) :** बाजार में जमाखोरी द्वारा वस्तुओं की कृत्रिम कमी पैदा करके उनकी कीमतों को बढ़ाकर लाभ कमाने को काला बाजार कहते हैं।
- **काला धन (Black money) :** जिस धन का हिसाब-किताब अधिकारियों से छिपाकर रखा जाता है, उसे काला धन कहते हैं।
- **बुरा ऋण (Bad debt) :** वह ऋण जिसकी वसूली संभव न हो अथवा संदिग्ध हो, बुरा ऋण माना जाता है।
- **ब्रिज लोन (Bridge loan) :** कंपनियाँ प्रायः शेयर तथा डिबेंचर जारी करके पूंजी का विस्तार करती हैं। कंपनी को शेयर जारी करके पूंजी जुटाने में तीन माह या उससे भी अधिक समय लगता है। इस समयावधि में अपना कार्य जारी रखने के लिये कंपनियाँ बैंकों से आंतरिक अवधि के लिये ऋण प्राप्त कर लेती हैं। इस प्रकार के ऋण को ब्रिज लोन कहते हैं।
- **ब्लू चिप (Blue chip) :** जिन कंपनियों का प्रबंध अत्यधिक कुशल तथा सुदृढ़ है, उन कंपनियों के शेयरों के लिये ब्लू चिप शब्द का प्रयोग किया जाता है। इनको बेचने तथा खरीदने में कोई कठिनाई नहीं होती।
- **ब्लू बॉक्स (Blue box) :** कृषि समझौते के अनुसार विभिन्न देश उत्पादन के उद्देश्य से कुछ सीमा तक सब्सिडी की अनुमति देते हैं, जैसे-बिजली, सिंचाई, उर्वरक आदि आगतों में दी जाने वाली सब्सिडी। इस सब्सिडी को ही ब्लू बॉक्स कहते हैं।
- **ब्लू कॉलर जॉब (Blue collar job) :** द्वितीयक क्षेत्र से संबद्ध ऐसे श्रमिकों को जो उत्पादन-प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध होते हैं, उन्हें ब्लू कॉलर जॉब कहा जाता है।

डी.एल.पी. बुकलेट्स की विशेषताएँ

- आयोग के नवीनतम पैटर्न पर आधारित अध्ययन सामग्री।
- पैराग्राफ, बुलेट फॉर्म, सारणी, फ्लोचार्ट तथा मानचित्र का उपयुक्त समावेश।
- विषयवस्तु की सरलता, प्रामाणिकता तथा परीक्षा की दृष्टि से उपयोगिता पर विशेष ध्यान।
- क्विक रिवीजन हेतु प्रत्येक अध्याय में महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन।
- प्रत्येक अध्याय के अंत में विगत वर्षों में पूछे गए एवं संभावित प्रश्नों का समावेश।

Website : www.drishtiIAS.com

E-mail : online@groupdrishti.com



DrishtiIAS



YouTube Drishti IAS



drishtiiias



drishtithevisionfoundation

641, First Floor, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009

Phones : 8750187501, 011-47532596